Regarding need to announce a special financial package to promote industrialisation in Bihar-Laid

श्री अरुण भारती (जमुई) : मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराने मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिससे बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों को ऐतिहासिक आर्थिक नुकसान हुआ है । यह मुद्दा 'मालभाड़ा समानीकरण नीति' (Freight Equalisation Policy) से जुड़ा है । 1952 में लागू की गई इस अदूरदर्शी नीति के तहत, केंद्र सरकार देश में कहीं भी फैक्ट्री लगाने के लिए खनिजों के परिवहन पर सब्सिडी देती थी । इस नीति ने बिहार जैसे खनिज-संपन्न राज्यों का प्राकृतिक और प्रतिस्पर्धी लाभ छीन लिया । जहाँ उद्योग खनिजों के स्रोत के पास लगने चाहिए थे,वे बंदरगाहों और बाज़ारों के पास लगने लगे । इससे इन राज्यों में औद्योगिक विकास की गति पूरी तरह से रुक गई । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रचुर खनिज संसाधन और उपजाऊ भूमि होने के बावजूद, बिहार और अब झारखंड भी,विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए । यह एक ऐतिहासिक अन्याय है जिसने पूर्वी भारत की आर्थिक कमर तोड़ दी । मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस नीति से हुए दशकों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए और यहाँ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की जाए । यह पैकेज बिहार को न्याय देगा ताकि देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके ।